

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य राजस्व आयुक्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

राजस्व अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: ०२ जून, 2009

विषय:-मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड के अनावासीय भवनों के अतिरिक्त कार्यों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1413/सी0आर0सी0/2008 दिनांक 20.01.2009 एवं शासनादेश संख्या-1942/18(1)/2008 दिनांक 20.08.2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 12वां वित्त आयोग द्वारा राज्य स्तरीय अवसंरचना हेतु संस्तुत अनुदान के अन्तर्गत मुख्य राजस्व आयुक्त कार्यालय, उत्तराखण्ड के निर्माणाधीन अनावासीय भवनों में अतिरिक्त कार्यों के निर्माण हेतु शासन को उपलब्ध कराये गये आगणन लागत रु0 61.79 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रु0 58.97 लाख की लागत पर उच्च स्तरीय समिति अनुमोदन के क्रम में प्रश्नगत कार्य की प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये वित्तीय वर्ष 2009-10 में रु0 58.97 लाख (रु0 अठ्ठावन लाख सत्तानवे हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. कार्य करने से पूर्व मदवार दर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर तथा जो दरें शिड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन आवश्यक होगा।
2. कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी राशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
4. एक मुश्त प्राविधानों को कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।
5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
6. निर्माण सामग्री क्रय करने से पूर्व मानकों एवं स्टोर पर्येज नियमों का कड़ाई से पालन किया जाये।
7. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता से कार्य स्थल का भली भांति निरीक्षण अवश्य लिया जाए तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

8. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाए तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाए।
 9. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219 (2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
 10. निर्माण कार्य उत्तराखण्ड प्रॉक्योरमेंट रूल्स 2008 के प्राविधानों के अन्तर्गत कराया जायेगा।
 11. निर्माण कार्य दिनांक 31.12.2008 तक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक 10.01.2010 तक उपलब्ध कराया जायेगा।
 12. गत वर्ष अवमुक्त धनराशि रू0 205.92 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 55.92 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।
- 2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्यय की अनुदान संख्या-07 के लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य भवन-आयोजनागत-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें-0101-12वें वित्त आयोग के अन्तर्गत अवस्थापना विकास-24-वृहत निर्माण के नामें डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-36p/XXVII(5)/2009 दिनांक 26 जून, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुभाष कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 93 & (1)/XVIII(1)/2009 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. अपर सचिव, बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय देहरादून।
5. जिलाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग-5
9. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।